

आउटसोर्स

प्रदेश सरकार ने दिपावली के पर्व को देखते हुए आउट सोर्स, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और मल्टी टाक्स वर्करों को भी 28 अक्टूबर को वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 85 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गई और अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आर्थिक संकट को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने संजौली में मस्जिद कमेटी द्वारा मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को स्वयं तोड़ने की शुरुआत करने पर कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष खुद मस्जिद तोड़ने के लिए आगे आया है जो सराहनीय कदम है।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण विभाग और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच आज सुन्नी-लूहरी सड़क के विस्तारीकरण की परियोजना को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एस जेवीएन इस सड़क का घरेलू नाला खैरा से ढली-देवीधर तक विस्तारीकरण करेगा। इस कार्य पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस समझौते से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। एस जेवीएन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सुशील कुमार शर्मा ने इस मौके पर निगम द्वारा सुन्नी-लूहरी क्षेत्र में सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

मस्जिद

नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम आज से आरम्भ हो गया। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद की देखरेख में हो रहा है। मोहम्मद लतीफ ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए अभी तक पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद तोड़ने का काम आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य

के लिए काफी अधिक पैसे की जरूरत है। इस कारण इस कार्य में तीन से चार माह का समय लग सकता है। इस बीच शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का अवैध हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद कमेटी को अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए पैसे की कमी है तो वे निगम कोर्ट को पत्र लिख सकते हैं। उन्होंने हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य में साम्प्रदायिक सोहार्द बनाए रखने के लिए इसे बेहतर पहल करार दिया है। नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद की अवैध रूप से बनी तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस कार्य के लिए निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दो महीने का समय दिया है। बाद में अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी थी जो अब मिल गई है।

अग्निवीर

मंडी में 18 से 24 नवम्बर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। एडीसी मंडी रोहित राठौर ने इस भर्ती रैली की तैयारियों की आज समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सेना को रैली के सफल आयोजन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल डी.एस. सामंत ने इस मौके पर कहा कि इस भर्ती रैली में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से 3 हजार 3 सौ से अधिक युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 7 दिनों तक चलने वाली इस भर्ती रैली में हर रोज लगभग 7 सौ युवा भर्ती के लिए पहुंचेंगे।

योग शिविर

ऊना के उपायुक्त व जिला रैडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष जतिन लाल ने कहा है कि जिले में सामार्थ्य योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में सात दिवसीय निशुल्क योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस योजना के माध्यम से ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का आयोजन सभी पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य योग के माध्यम से लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना और स्वस्थ व सशक्त समाज का निर्माण करना है।

कैबिनेट

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल 22 अक्टूबर को शिमला में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। दिवाली से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक से कई वर्गों को उम्मीदें हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद कर्मचारियों को रिझाने वाले फैसले ले रहे हैं।
